भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2341

जिसका उत्तर 16 मार्च, 2017 को दिया जाना है ।

विद्युत क्षेत्र में निजी निवेश

2341. डॉ. उदित राजः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ग्यारहवीं और बारहवीं योजना अवधियों के दौरान विद्युत क्षेत्र में कितना सरकारी और निजी निवेश किया गया;

(ख) क्या अगले पांच वर्षों के दौरान देश में अतिरिक्त विद्युत आवश्यकताओं का आकलन करने हेतु कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ पहचान किए गए संसाधनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सभी के लिए चौबीस घंटे बिजली की आपूर्ति के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु विद्युत क्षेत्र में सरकारी और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम प्रस्तावित हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : 11वीं और 12वीं योजना अवधियों के दौरान विद्युत क्षेत्र (नवीकरणीय ऊर्जा को छोड़कर) में किए गए सार्वजनिक और निजी निवेश की राशि निम्नवत हैः

(रुपए करोड़ में)

क्षेत्र	ग्यारहवीं योजना	बारहवीं योजना
सार्वजनिक	3,92,110	6,98,191
निजी	3,01,370	4,42,588
कुल	**6,93,480**	**11,40,779**

(ख) और (ग) : देश की विद्युत मांग का आवधिक मूल्यांकन विगत वर्षों में प्रणाली संबंधी आकस्मिक वास्तविक विद्युत मांग, सरकार की विभिन्न नीतियों एवं कार्यक्रमों, भविष्य के लिए नियोजित विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों आदि को ध्यान में रखते हुए इलैक्ट्रिक पावर सर्वेक्षण समिति (ईपीएससी) द्वारा किया जाता है। नवीनतम विद्युत मांग पूर्वानुमान रिपोर्ट भारत का 19वां इलैक्ट्रिक विद्युत सर्वेक्षण है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित किए गए 19वें इलैक्ट्रिक विद्युत सर्वेक्षण (ईपीएस) रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2016-17, 2021-22 तथा 2026-27 के लिए देश की इलैक्ट्रिक ऊर्जा मांग (ईईआर) तथा व्यस्ततम मांग नीचे दी गई हैः

वर्ष	**इलैक्ट्रिकल ऊर्जा आवश्यकता (एमयू)**	**व्यस्ततम मांग (मेगावाट)**
2016-17	1160429	161834
2021-22	1566023	225751
2026-27	2047434	298774

51218.59 मेगावाट की क्षमता के साथ ताप विद्युत उत्पादन, 12,217.5 मेगावाट की क्षमता के साथ जल विद्युत उत्पादन और 7700 मेगावाट की क्षमता के साथ न्यूक्लियर उत्पादन निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अतिरिक्त, 44100 मेगावाट न्यूक्लियर क्षमता को भी चिन्हित किया गया है, जिसके लिए भारत सरकार (जीओआई) द्वारा "सैद्धांतिक" अनुमोदन प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 175 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है।

(घ) : भारत सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न पहलें की गई हैं:

i. उत्पादन तथा पारेषण में निजी क्षेत्र भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रावधानों के साथ वर्ष 2005 में राष्ट्रीय विद्युत नीति तथा दिनांक 28.01.2016 को संशोधित प्रशुल्क नीति अधिसूचना।

ii. विद्युत उत्पादन (परमाणु ऊर्जा को छोड़कर), पारेषण, वितरण एवं व्यापार की परियोजनाओं के लिए स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति प्रदान की जाती है। स्वचालित मार्ग के अंतर्गत केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार) विनियम, 2010 के अंतर्गत पंजीकृत विद्युत एक्सचैंजों में 49% तक के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी जाती है।

iii. सरकार ने डिस्कॉमों के प्रचालनात्मक एवं वित्तीय बदलाव के लिए दिनांक 20.11.2015 को उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) अधिसूचित की है।

****